कुछ काम की बात करो, पैसा लाओ

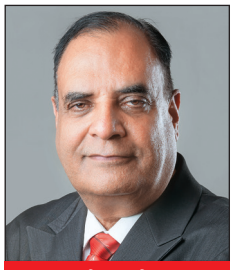

आलोक मेहता

'हर हाथ को काम, हर मुंह को रोटी, हर खेत को पानी, हर तन को कपड़ा, हर सिर पर मकान- बाकी सब बात खोटी।' इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी, लोकदल, समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न दलों को नब्बे के दशक में कांग्रेस विरोधी राजनीतिक आंदोलन में सफलता दिलाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी देवीलाल, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को प्रदेशों में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुषमा स्वराज, नरेंद्र मोदी, के.सी. त्यागी जैसे नेताओं के सहयोग से जन-आंदोलनों की हवा बनाने में सहायता मिली। दूसरी पंक्ति के वही नेता आज राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर सत्ता के केंद्र हैं। रोटी, कपड़ा, मकान से भी ज्यादा जरूरी है- रोजगार। गांव के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से लेकर मुंबई, बेंगलूरु, दिल्ली -गुरुग्राम- जैसे महानगरों-शहरों की अत्याधुनिक कंपनियों तक की नौकरी के बल पर ही आर्थिक विकास तेज हो सकता है। नई पीढ़ी को पुराने नारों, आंदोलनों से अधिक 2014 के चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी द्वारा एक करोड़ लोगों को रोजगार देने, महंगाई से बड़ी राहत और हर घर-गांव में खुशहाली दिलाने के वायदे से मतलब है। उन्हें मालूम है कि विदेशों से काला धन वापस लाकर हर खाते में 15 लाख रुपये दिलवाना कठिन है लेकिन अपने ही देश में रोजगार मिलने और महंगाई से निजात मिलने की बड़ी उम्मीद रही है। लेकिन उन्हें निराशा मिल रही है। देश में अब युवाओं के लिए जे.पी., समाजवादी या वामपंथी संगठनों की ओर से कोई बड़ा आंदोलन छेड़ने वाला संगठन भी नहीं है। अब तो जाति, धर्म, राष्ट्रवाद (भारत माता की जय) जैसे मुद्दों को गर्माकर राजनीति हो रही है। स्वयं मोदी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से देश-दुनिया को पता चल रहा है कि केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं, महत्वपूर्ण शहरी औद्योगिक क्षेत्रों में नए रोजगार मिलने की स्थिति पिछले वर्षों से बदतर हो गई है।

छाया: ए.पी.

भारत सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार टेक्सटाइल, लेदर, मेटल, ऑटोमोबाइल, जेम्स-ज्वैलरी, ट्रांसपोर्ट, आई.टी., हैंडलूम क्षेत्र में वर्ष 2015 में केवल 1 लाख 35 हजार लोगों को नौकरियां मिल सकीं। यह पिछले रोजगार रिकॉर्ड से 67 प्रतिशत की गिरावट है।

भारत सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार टेक्सटाइल, लेदर, मेटल, ऑटोमोबाइल, जेम्स-ज्वैलरी, ट्रांसपोर्ट, आई.टी., हैंडलूम क्षेत्र में वर्ष 2015 में केवल 1 लाख 35 हजार लोगों को नौकरियां मिल सकीं। यह पिछले रोजगार रिकॉर्ड से 67 प्रतिशत गिरावट है। इन्हीं क्षेत्रों में वर्ष 2014 में 4 लाख 42 हजार लोगों को नौकरियां मिली थीं। 2015 में नौकरियां मिलनी दूर, अंतिम तिमाही में ऐसी कंपनियों से 20 हजार लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। सरकार स्वयं मानती है कि देश में हर साल करीब 1 करोड़ 20 लाख शिक्षित युवक नई नौकरी के लिए आते हैं। कांग्रेस गठबंधन सरकार के दौरान भारी भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे लेकिन युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलते रहे। मोदी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से ही इस बात की पुष्टि हो रही है कि 2013 में 4 लाख 19 हजार, 2012 में 3 लाख 21 हजार, 2011 में 9 लाख 29 हजार, 2010 में 8 लाख 70 हजार, 2009 में 10 लाख 28 हजार युवाओं को ऐसे चुनिंदा सात क्षेत्रों की कंपनियों में नौकरियां मिली थीं। अब सरकार के डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप्स के आकर्षक नारों और अभियानों के बावजूद नई नौकरियां मिलने के बजाय घट रही हैं। इतने विदेशी दौरों, चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, सऊदी अरब तक से बड़े समझौतों के बावजूद पूंजी निवेश में 70 प्रतिशत गिरावट आई है। बड़े औद्योगिक समूहों के प्रमुख तक सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो पाने के कारण लगभग 10 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट लटके हुए हैं।

यह स्थिति केवल राजनीतिक सत्ता व्यवस्था के लिए ही नहीं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की जमीन को खोखली कर दूरगामी खतरों की घंटी बजा रही है। नारों, भाषणों, धुआंधार सरकारी प्रचार से करोड़ों युवाओं के परिवारों के पेट नहीं भरे जा सकते हैं। दो वर्षों में पहले से सक्रिय निवेशकों का दबाव बढ़ने से स्टार्ट अप्स में नौकरियां कम होती जा रही हैं। किसानों को मेहनत और उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। जिनके पास खेती लायक जमीन है, जब वे ही बड़ी संख्या में आत्महत्या करने लगे हैं तो भूमिहीन मजदूरों की हालत अधिक खराब होनी ही है। संपन्न कहे जाने वाले महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के सैकड़ों गांवों में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। सरकार यह तर्क दे सकती है कि अगले तीन से दस वर्षों में स्थिति सुधर जाएगी लेकिन लोग तात्कालिक राहत के लिए नए रोजगार की अपेक्षा रखते हैं। एक सौ करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड यदि तरक्की की निशानी हैं तो यह भी स्मरण रखना होगा कि उन्हें अपने जीने, खाने-पीने, मेहनत मजदूरी से कमाई और सिर छिपाने की सुविधा अधिकार की तरह मिलने की अपेक्षा भी होगी। समय रहते नारों को व्यवहार में लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास तेज करने होंगे।

www.outlookhindi.com